

रजिस्टर्ड नं० न०-33/एस०एम० 14/92.



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, बुधवार, 16 सितम्बर, 1992/25 भाद्रपद, 1914

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 सितम्बर, 1992

संख्या एल० एल० आर०-डी० (6)24/92-लेजिस्लेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 16 सितम्बर, 1992 को प्रख्यापित

हिमाचल प्रदेश शिक्षा संस्था (रैगिंग प्रतिषेध) अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या 5) को, संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरत/-  
सचिव (विधि)।

## हिमाचल प्रदेश शिक्षा संस्था (रैगिंग प्रतिषेध) अध्यादेश, 1992

भारत गणराज्य के तैतालीसवें वर्ष में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रख्यापित ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की शिक्षा संस्थाओं में रैगिंग की बुराई के निवारण का उपबन्ध करने के लिए अध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है ;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश शिक्षा संस्था (रैगिंग प्रतिषेध) अध्यादेश, 1992 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं

(क) “शिक्षा संस्था” से, कोई विश्वविद्यालय, विद्यालय से सहबद्ध या इस द्वारा अनुरक्षित कोई महाविद्यालय, हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध माध्यमिक शिक्षा देने वाला कोई स्कूल, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध तकनीकी शिक्षा देने वाला कोई स्कूल, पालिटैक्निक या संस्था अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी अन्य संस्थाएं भी हैं, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएं ;

(ख) “प्रभारी अधिकारी” से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत वे व्यक्ति हैं जिन्हें :—

(i) विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में किसी महाविद्यालय का प्रधानाचार्य, छात्र निवास का प्रधान, संकायाध्यक्ष, अध्यापन विभाग या संस्था का विभागाध्यक्ष, महाविद्यालय का प्राधिकारी, किसी छात्रावास या कन्टीन का वार्डन या प्रबन्धक (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए), छात्र कल्याण अधिकारी, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों के रूप में नियुक्त, किया गया है ;

(ii) विश्वविद्यालय से भिन्न शिक्षा संस्था के सम्बन्ध में जिसे शिक्षा संस्था का प्रधानाचार्य, मुख्याध्यक्ष, प्रबन्धक या अध्यापक या ऐसी शिक्षा संस्था द्वारा चलाए गए छात्रावास या कन्टीन का वार्डन या प्रबन्धक (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए) के रूप में नियुक्त किया है ;

(ग) "रैगिंग" से कोई कार्य, आचरण या व्यवहार जिस द्वारा वरिष्ठ विद्यार्थियों की अधिष्ठाई शक्ति या हैसियत को, नए भर्ती किए विद्यार्थियों पर या ऐसे विद्यार्थियों पर जिन्हें किसी प्रकार से कनिष्ठ या निम्नतर समझा जाता है, प्रयोग में लाया जाता है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित सामूहिक कार्य या व्यवहार है,—

- (i) जिसमें शारीरिक हमला या धमकी अथवा शारीरिक बल का प्रयोग शामिल है, या ;
- (ii) जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित विद्यार्थियों की प्रतिष्ठा, सम्मान और आदर का अतिक्रमण करता है, या
- (iii) जो विद्यार्थियों को उपहास और अपमान का विषय बनाता है तथा उनके आत्म-सम्मान को प्रभावित करता है ;
- (iv) जिसमें मौखिक गाली-गलोच और छेड़-छाड़, अशिष्ट अंगविक्षेप और अश्लील व्यवहार हो ।

रैगिंग का  
प्रतिषेध ।

3. (1) कोई भी व्यक्ति शिक्षा संस्था के परिसर में या बाहर अथवा इसके छात्रावास, कैन्टीन, इसके आस-पास के सार्वजनिक स्थान याइ सको जाने वाली सड़क अथवा परिवहन में भी, किसी भी रूप में रैगिंग नहीं करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति जो उप-धारा (1) का उल्लंघन करता है, दोषसिद्ध पर, कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

कुछ व्यक्तियों  
का रैगिंग की  
घटनाओं की  
जांच-पड़ताल  
और रिपोर्ट  
करने का  
कर्तव्य ।

4. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी संविदा में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यक्ति जो किसी शिक्षा संस्था का प्रभारी अधिकारी है या जो, उसमें अनुशासन बनाए रखने के सम्बन्ध में, किसी शिक्षा संस्था की सेवा में है या उसका वेतन भोगी है या उससे पारिश्रमिक पाता है, रैगिंग की घटना होने पर तुरन्त कार्रवाई करने और विश्वविद्यालय की दशा में, कुलपति या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को या विश्वविद्यालय से भिन्न संस्था की दशा में, शिक्षा संस्था के प्रधान को उनकी पहचान जो रैगिंग में लगे हों और घटना की प्रकृति की रिपोर्ट करने को बाबद्ध होगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) का उल्लंघन करता है, दोषसिद्ध पर, कारावास से जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

धारा 3 के  
अधीन अप-  
राधों का  
दुष्प्रेरण ।

5. जो कोई भी शिक्षा संस्था में उचित अनुशासन बनाए रखने के लिए सीधे तौर पर या मुख्य तथा पर्यवेक्षण का प्रभारी अधिकारी होते हुए, जानबूझ कर जांच-पड़ताल और रिपोर्ट नहीं करता है, धारा-3 के अधीन अपराध करने में मौनानुमति देता है या दुष्प्रेरित करता है, दोनों में से किसी प्रकार क कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

अपराधों का  
संक्षेप, जमान-  
तीय और  
शमनीय होना ।

6. इस अध्यादेश के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, जमानतीय और न्यायालय की अनुमति से शमनीय होगा ।

7. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस आध्यादेश के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक रैगिंग विरोधी दस्ते गठित कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना में वे क्षेत्र, जिन में इस प्रकार गठित ऐसे रैगिंग विरोधी दस्ते अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, विनिर्दिष्ट करेगी। रैगिंग विरोधी दस्ते गठित करने की शक्ति।

(2) उप धारा (1) के अधीन गठित रैगिंग विरोधी दस्ता व्यक्तियों की ऐसी संख्या से और ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर कार्य करेगा जैसी कि विाहत की जाएं और रैगिंग के नियंत्रण और निवारण के सम्बन्ध में इसके सदस्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जैसी कि राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अधीन उन्हें प्रदत्त की जाएं।

8. राज्य सरकार, यदि इसका समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, उसमें कथित कारणों से लिखित आदेश द्वारा, शिक्षा संस्थाओं को उन द्वारा अनुसरण किए जाने वाले साधारण अनुदेश दे सकेगी और ऐसे अनुदेशों के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (1970 का 17), हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का 4), हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 (1968 का 14), हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 14) और सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) में किसी बात के होते हुए भी ऐसे प्रारूप में और ऐसी अवधि के भीतर जैसी कि ऐसे आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाए, विद्यार्थियों में अनुशासन बढाए रखने और रैगिंग के प्रतिषेध और उसके लिए दण्ड से सम्बन्धित अध्यादेश, परिनियम, विनियम, नियम, उपविधियां बनाने और उनमें संशोधन करने के निदेश भी हैं। राज्य सरकार को निदेश देने की शक्ति।

9. इस अध्यादेश के उपबन्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (1970 का 17) और हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का 4) के अधीन विरचित परिनियमों के अल्पीकरण में नहीं अपितु उनके अतिरिक्त होंगे। उपबन्धों का कतिपय नियमों का अल्पीकारक न होना।

10. राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

11. धारा-8 के अधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश और धारा 10 के अधीन बनाए गए नियम, जारी किए जाने या बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के जिसमें यह इस प्रकार रखा जाता है या पूर्वोक्त सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा, यथा स्थिति, उस नियम या आदेश में कोई परिवर्तन करती है या यह विनिश्चय करती है कि नियम या आदेश बनाया या जारी नहीं किया जाना चाहिए तो, यथास्थिति, नियम या आदेश तत्पश्चात् ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या तिष्ठप्रभाव हो जाएगा। किन्तु, यथा-स्थिति, नियम या आदेश के ऐसे परिवर्तित या तिष्ठप्रभाव होने से उसके अधीन पहल की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियमों और आदेशों का रखा जाना।

## AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

## ORDINANCE NO. 5 OF 1992.

THE HIMACHAL PRADESH EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
(PROHIBITION OF RAGGING) ORDINANCE, 1992

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Forty-third Year of the Republic of India.

An Ordinance to provide for prevention of the evil practice of ragging in Educational Institutions in the State of Himachal Pradesh;

Whereas the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make and promulgate the following Ordinance:—

Short title  
and commen-  
cement.

1. (1) This ordinance may be called the Himachal Pradesh Educational Institutions (Prohibition of Ragging) Ordinance, 1992.

(2) It shall come into force at once.

Definitions.

2. In this Ordinance, unless the context otherwise requires,—

(a) “educational institution” means any University, any College affiliated to or maintained by the University, any College affiliated to or maintained by the University, any School imparting secondary education affiliated to the Himachal Pradesh Board of School Education, any School, Polytechnic or institution imparting technical education affiliated to the Himachal Pradesh Board of Technical Education and includes such other institutions as may be notified by the State Government in the Official Gazette;

(b) “Officer-in-Charge” means and includes persons—

(i) in relation to a University, who are appointed as the Principals of Colleges, Heads of Halls, Deans of Faculties, Heads of Teaching Departments or the institutions, the authorities of the Colleges, Wardens or Managers (by whatever name called) of Hostels or canteens the Students, Welfare Officer or the Librarians of the College and University Libraries;

(ii) in relation to an educational institution, other than a University, who is appointed as the Principal, Headmaster, Manager or teacher of the educational institution;

(c) "ragging" means any act, conduct or practice by which dominant power or status of senior students is brought to bear on students freshly enrolled or students who are in any way considered junior or inferior by other students and includes individual or collective acts or practices which—

- (i) involve physical assault or threat or use of physical force; or
- (ii) violate the status, dignity and honour of students belonging to scheduled castes or tribes; or
- (iii) expose students to ridicule and contempt and affect their self-esteem;
- (iv) entail verbal abuse and aggression, indecent gestures and obscene behaviour.

3. (1) No person shall practise ragging in any form, within or outside the premises of an educational institution or in its hostels, canteens as well as on a public place in its vicinity or on a road or transport leading to it.

Prohibition of ragging.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

4. (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or in any contract, every person who is the officer-in-charge of the educational institution or who is in the service or pay of or remunerated by any educational institution to do any work assigned to him in connection with the maintenance of discipline therein, shall be bound to take immediate action on the occurrence of any incident of ragging and to make report to the Vice-Chancellor or to any other officer authorised by him, in case of the University, or the Head of the Educational Institution, in case of the institution other than the University, the identity of those who have engaged in ragging and the nature of the incident.

Duties of certain persons to check and report incidents of ragging.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or a fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

5. Whoever being an officer, directly or primarily in-charge of supervision for the proper maintenance of discipline in the educational institution, knowingly omits to check and report or connives or abets the commission of the offence under section 3 shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine, or with both.

Abetment of offences under section-3.

6. Every offence under this Ordinance shall be cognizable, bailable and compoundable with the permission of the court.

Offences to be cognizable, and bailable, and compoundable. Power to constitute anti-ragging squads.

7. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, constitute one or more anti-ragging squads for the purposes of this Ordinance and shall specify in such notification the area in which such anti-ragging squad, so constituted, shall exercise its powers.

(2) The anti-ragging squad, constituted under sub-section (1), shall consist of such number of persons and shall function on such terms and conditions as are prescribed ; and in relation to the control and prevention of ragging its members shall exercise such powers as may be conferred upon them under the provisions of any law for the time being in force in the State.

Power of the State Government to give directions.

8. The State Government may, if satisfied that the public interest so requires, by order in writing for reasons to be stated therein, give to the educational institutions general instructions to be followed by such institutions and such instructions may, not with standing anything contained in the Himachal Pradesh University Act, 1970 (17 of 1970) and the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (4 of 1987), the Himachal Pradesh Board of School Education Act, 1968 (14 of 1968), the Himachal Pradesh Board of Technical Education Act, 1986 (14 of 1986) and the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), include directions to make or amend any Ordinances, Statutes, regulations, rules, by-laws relating to the maintenance of discipline among students and prohibition of and the punishment for ragging, in such form and within such period as may be specified in such order.

Provisions not to be derogatory to certain laws.

9. The provisions of this Ordinance shall be in addition to and not in derogation of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), and the statutes framed under the Himachal Pradesh University Act, 1970 (Act No. 17 of 1970) and the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (4 of 1986).

Power to make rules.

10. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Ordinance.

Laying of rules and orders.

11. Every order issued under section 8 and rule made under section 10 shall be laid as soon as may be after it is issued or made before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of the session in which it is so laid or the sessions aforesaid, the Assembly makes any modification in the rule, or as the case may be in the order, or decides that the rule or the order, as the case may be, should not be issued or made, the rule or as the case may be the order, shall, thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or as the case may be under that order.

SHIMLA.

The 16th September, 1992.

VIRENDER VERMA,

Governor.